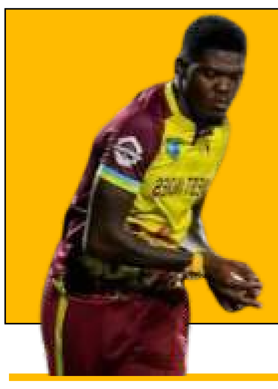

अल्जारी जोसफ ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया

Page-04

tv भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को नहीं होगा रिलीज

Page-05

सेल्फी वीडियो से छात्रों तक पहुंचे PM मोदी बोले– 'पेपर लीक मामूली नहीं'।

नई दिल्ली। NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 11:52 बजे एक सेल्फी वीडियो संदेश जारी कर सीधे देश के छात्रों से संवाद किया। करीब तीन मिनट के इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है और इससे लाखों छात्रों तथा उनके परिवारों को गहरी पीड़ा हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने मामले में तेजी से कदम उठाए हैं। पेपर लीक से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और जांच लगातार जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। अगले ही दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी भी दे दी। प्रधानमंत्री का यह संवाद शैली के लिहाज से भी अलग रहा। आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों या आधिकारिक संबोधनों के बजाय उन्होंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया एक सेल्फी वीडियो साझा किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह तरीका खास तौर पर युवाओं और डिजिटल माध्यम से जुड़े दर्शकों तक सीधे पहुंचने की रणनीति का हिस्सा था।

सोनम वांगचुक ने खत्म की 26 दिन की भूख हड़ताल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन रहेगा जारी

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने राहत जताई है, लेकिन साथ ही साफ कर दिया है कि उसका आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आंदोलन वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी मुख्य मांग पर फैसला नहीं लेती।अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया मंच X पर सोनम वांगचुक का आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्होंने 26 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान असाधारण साहस, धैर्य और त्याग का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वांगचुक के संघर्ष ने देशभर के युवाओं की आवाज को मजबूत किया है।मीडिया से बातचीत में दिपके ने कहा, "हमारे लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही सबसे बड़ी मांग है। इसके अलावा कोई भी विकल्प स्वीकार नहीं है। यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं का आंदोलन है। इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।"उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखा था। दिपके के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उनसे मिल सके, लेकिन विपक्षी सांसदों और CJP के प्रतिनिधियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है, लेकिन आंदोलन की दिशा अब भी वही रहेगी।कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिपके ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह युवाओं का है और इसका संचालन किसी विपक्षी दल द्वारा नहीं किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और सरकार पर दबाव तब तक बना रहेगा, जब तक प्रमुख मांगें पूरी नहीं हो जातीं।इस बीच, सरकार और CJP के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है। संगठन ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता के लिए 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया' को तटस्थ स्थान के रूप में चुना गया है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब सरकार ने वांगचुक की कुछ मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है और दोनों पक्षों के बीच आगे भी वार्ता जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।

RJD को बड़ा झटका मृत्युंजय तिवारी BJP में शामिल

पटना। बिहार की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण कर ली। लंबे समय तक RJD का प्रमुख चेहरा रहे तिवारी ने पार्टी नेताओं की मौजूदगी में BJP की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उनके इस कदम को बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।मृत्युंजय तिवारी ने 16 जुलाई को RJD से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के दौरान उन्होंने पार्टी के कामकाज के तरीके, संगठन में बढ़ती उपेक्षा और लगातार नजरअंदाज किए जाने को अपना मुख्य कारण बताया था। उनके इस्तीफे के बाद से ही BJP में शामिल होने की चर्चाएं तेज थीं, जिन पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है।RJD में रहते हुए मृत्युंजय तिवारी पार्टी के सबसे सक्रिय प्रवक्ताओं में शामिल रहे। उन्होंने वर्षों तक टीवी डिबेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। उन्हें RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता रहा है। तिवारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने हमेशा उन्हें सम्मान और सहयोग दिया, लेकिन पिछले कुछ समय में पार्टी के भीतर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसने उन्हें गहरा आहत किया। BJP में शामिल होने के बाद तिवारी ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में, जब RJD अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, तब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाया था।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले–

'धर्मेंद्र प्रधान अपराधी शिक्षा मंत्री, इस्तीफा देना ही होगा'

नई दिल्ली। NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को "अपराधी शिक्षा मंत्री" बताते हुए कहा कि उन्हें तत्काल पद छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था में आई अव्यवस्था और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है।मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने छात्रों की ओर से तीन प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखीं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।राहुल गांधी ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था के विफल होने का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी वजह से हजारों छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। इसलिए उन्हें अपने पद से हटना ही होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की लापरवाही से पेपर लीक हुआ, उन्हें तुरंत नौकरी से निकाला जाना चाहिए।प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रदर्शनकारी युवक को मीडिया के सामने पेश किया। उनका दावा था कि 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान युवक पैलेट गन की चपेट में आकर घायल हुआ और उसकी आंख को गंभीर नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर रही है, जबकि घायल छात्र इसकी सच्चाई का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह युवक पुलिस भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी था, जिसकी परीक्षा भी कथित पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुई।राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया और हजारों युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इधर, इसी दिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की।

पेपर लीक पर सख्ती की तैयारी, केंद्रीय कैबिनेट ने नए विधेयक को दी मंजूरी

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर बढ़ते विवाद और छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले एक प्रारूप विधेयक (ड्राफ्ट बिल) को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। नए कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ मौजूदा कानूनों से अधिक कठोर दंड सुनिश्चित करना है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी तथा छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत किया जाएगा। इस बीच, NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

tv भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2-3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

CJI सूर्यकांत ने मीडिया रिपोर्टों को बताया भ्रामक, बोले– याचिका दायर ही नहीं हुई थी

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में कोई रिट याचिका दायर ही नहीं की गई थी, बल्कि केवल एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) भेजा गया था। इसलिए सुनवाई से इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता।सुप्रीम कोर्ट में जरूरी मामलों की लिस्टिंग के दौरान CJI ने कहा कि पिछले दो दिनों से कुछ मीडिया संस्थानों ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए यह खबर चला दी कि अदालत ने मामले को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत और गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करार दिया। CJI ने कहा कि सुबह 10 बजे तक अदालत में इस मामले से संबंधित एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था। केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसे कानूनी रूप से रिट याचिका नहीं माना जा सकता।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी प्रतिनिधित्व को याचिका मानकर सुनवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने मीडिया से तथ्यात्मक और जिम्मेदार रिपोर्टिंग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि बिना सत्यापन के खबरें प्रकाशित करना न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भ्रम पैदा करता है।यह विवाद 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के नेतृत्व में हुए विरोध मार्च के बाद सामने आया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारी NEET-UG पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में छात्रों पर कथित पुलिस बर्बरता के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके पास वीडियो सबूत भी हैं।

BRICS 2026: भारत ने बांग्लादेश को दिया खास न्योता

रिश्तों में नई गर्माहट के संकेत

भारत ने नई दिल्ली में होने वाले BRICS 2026 शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।यह कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, व्यापारिक और क्षेत्रीय सहयोग को नई मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य टूरिस्ट वीजा सेवा भी दोबारा शुरू कर दी है, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों में सकारात्मक माहौल बना है।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। भारत ने BRICS समिट 2026 के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। यह न्योता ऐसे समय में आया है, जब दोनों देश अपने आपसी संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाली 18वीं BRICS समिट में ग्लोबल सहयोग, ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें इस बैठक में भारत ने बांग्लादेश को सदस्य देश या ऑब्जर्वर के रूप में नहीं, बल्कि विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने का अवसर दिया है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने पुष्टि की है कि भारत की ओर से मिले निमंत्रण को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय को आधिकारिक रूप से यह जानकारी मिली है। बता दें BRICS वर्तमान में 11 देशों का समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। हालांकि बांग्लादेश इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत ने उसे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है। माना जा रहा है कि भारत इस कदम के जरिए दक्षिण एशिया में सहयोग और आपसी भरोसा बढ़ाना चाहता है।BRICS 2026 की अध्यक्षता कर रहा भारत का मुख्य फोकस मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिर विकास पर है। ऐसे में पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत लगातार बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी को औपचारिक कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया था। यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक अहमियत को दिखाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में लंबे समय से साझेदारी रही है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। भारत ने करीब दो साल बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य टूरिस्ट वीजा सेवा दोबारा शुरू कर दी है। भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर के दौरे के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामान्य यात्रा वीजा के लिए आवेदन फिर से स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, जरूरी मेडिकल मामलों के लिए वीजा सुविधा पहले से जारी थी। यह फैसला दोनों देशों के आम नागरिकों, कारोबारियों और यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। BRICS समिट का निमंत्रण और वीजा सेवा की बहाली को भारत-बांग्लादेश संबंधों में सकारात्मक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया इस्तीफा

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया गया है। बांग्लादेशी संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉफ्रेंस बुलाई है। राष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण, बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज संभालेंगे, जब तक कि नया राष्ट्रपति पद नहीं संभाल लेता। मोहम्मद शहाबुद्दीन को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी माना जाता है। उन्होंने हाल में ही शेख हसीना से बात भी की थी, जिसके बाद वह विरोधियों के निशाने पर थे। उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के कहने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उन्हें सत्तारूढ अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध चुना गया था। उनका पांच साल का कार्यकाल अप्रैल 2028 में खत्म होने वाला था। लेकिन, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है।

बताया जा रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है।

सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना से करीबी के कारण उनकी कुर्सी गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद अटकलें हैं कि कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनका नाम शीर्ष संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहा है। हाल में ही ब्रिटेन में रहने वाले बांग्लादेशी पत्रकार जुल्करनैन साएर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार मौजूदा कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी को उत्तराधिकारी नामित कर सकती है।

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी

पेट्रोल पंप पर हुए बम विस्फोट के मामले में केवाईकेएल उग्रवादी को गिरफ्तार किया

इंफाल, 24 जुलाई मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मोइरांग स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुए बम विस्फोट के सिलसिले में एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) के एक सक्रिय सदस्य को बृहस्पतिवार को बिष्णुपुर जिले की तेरा उरक जांच चौकी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान 39 वर्षीय मयांगलंबम तोंबा सिंह के रूप में हुई है। वह चुराचांदपुर जिले के बिजांग खुनौ का निवासी है और फिलहाल फुबाला राहत शिविर में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि उसके पास से मैगजीन सहित नौ मिलीमीटर की एक पिस्तौल और अलग-अलग बोर के 11 कारतूस बरामद किए गए। सिंह इस वर्ष की शुरुआत में मोइरांग के एक पेट्रोल पंप पर हुए विस्फोट में कथित तौर पर शामिल था। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। सुरक्षा बलों ने एक अलग अभियान में प्रतिबंधित यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के संदिग्ध "वित्त प्रमुख" को चुराचांदपुर जिले के मोलनोम से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान एस. पलाल कुकी के रूप में हुई है। वह गोलीबारी और वसूली के कई मामलों में कथित तौर पर शामिल था।

यरूशलम में एक भारतीय नागरिका का शव अपार्टमेंट से बरामद किया गया

इजरायल के यरूशलम में एक भारतीय नागरिक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक कमरे में मृत अवस्था में मिला था और उसके आस-पास खून फैला हुआ था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी मृतक और हत्यारे की पहचान उजागर नहीं की गई है। पुलिस ने बताया कि यरूशलम में एक भारतीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सिलसिले में 31 वर्षीय इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक 40 वर्षीय भारतीय व्यक्ति गुरुवार को यरूशलम के कटामोन इलाके में मृत पाया गया। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित एक घर में फर्श पर पड़ा था और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था।इजरायली पुलिस प्रवक्ता यूनिट ने ईमेल से दिए एक जवाब में बताया, "यरूशलम के कटामोन इलाके में एक अपार्टमेंट में 40 वर्षीय भारतीय नागरिक के मृत पाए जाने की सूचना मिली। इसके बाद, मोरिया पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और फोरेंसिक जांचकर्ताओं के साथ प्रारंभिक जांच शुरू की।" पुलिस ने कहा, "घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि घटना आपराधिक प्रकृति की है।" पुलिस ने आगे कहा कि इजरायल पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही एलाट निवासी की पहचान कर उसे हत्या में संलिप्तता के संदेह में गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। भारतीय प्रवासी श्रमिक की पहचान भी अभी तक उजागर नहीं की गई है। घटना के बाद यरूशलेम जिला कमांडर अवशालोम पेल्ड भी घटनास्थल पर पहुंचे और जिला कमांडरों के साथ स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक आकलन के बाद, उन्होंने "जांच जारी रखने" का निर्देश दिया और इसे यरूशलेम जिला केंद्रीय इकाई (YAMAR) को सौंप दिया।

इमरान खान के बेटे ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की है। उनका कहना है कि उनके पिता, जो 1,100 दिनों से जेल में हैं, उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत है। 73 साल के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान अभी रावलपिंडी की अदियाला जेल में अकेले बंद हैं। उन्हें 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार किया गया था, जब इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तोशाखाना (राष्ट्रीय खज़ाना) मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। इसके बाद इमरान खान को कई और मामलों में भी गिरफ़्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, जिसकी वजह से वे लगातार जेल में हैं। कासिम खान ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे पिता इमरान खान को जेल में बंद हुए अब लगभग 1,100 दिन हो चुके हैं और मैंने और मेरे भाई ने मार्च के बाद से उनकी आवाज़ नहीं सुनी है। महीनों से हमें उनसे संपर्क करने की इजाज़त नहीं दी गई है। 26 वर्षीय कासिम खान अपने 29 वर्षीय भाई सुलेमान खान के साथ UK में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनकी सेहत और इलाज की सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है,

जबकि उनकी नज़र लगातार कमज़ोर होती जा रही है। उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत है, और परिवार या कानूनी तौर पर उनसे मिलने की इजाज़त न होने के कारण, हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी या भरोसा नहीं मिल पाता है। पाकिस्तान सरकार ने दिसंबर 2025 में इमरान खान की सभी तरह की मुलाकातों पर रोक लगा दी थी। यह रोक तब लगाई गई थी जब उन्होंने अपनी एक बहन के साथ मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति कहा था। कासिम खान ने कहा कि हाल ही में मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं उनसे आम चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा क्रिकेट, मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ और कौन सी नई फ़िल्में अच्छी हैं, वगैरह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग अपने चुने हुए नेता को आज़ाद देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने पिता की पहले से कहीं ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने कहा कि एक धांधली वाली, तानाशाही सरकार राजनीतिक विरोध को कुचल रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है और लाखों पाकिस्तानियों को अपने नेता चुनने के अधिकार से वंचित कर रही है, साथ ही जो लोग अपनी बात रखते हैं, उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है।

संपादक की कलम से

भारत का लोकतंत्र एक बार फिर बड़े जनआंदोलन के दौर से गुजर रहा है। NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में छात्रों का आक्रोश अब संसद से लेकर सड़कों तक दिखाई दे रहा है। विपक्ष सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बना रहा है, जबकि सरकार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और सख्त कानून लाने की बात कर रही है। सवाल केवल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर उनके भरोसे का है।पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले लगातार सामने आए हैं। इससे छात्रों के मन में यह भावना गहरी हुई है कि उनकी वर्षों की मेहनत कुछ लोगों की लापरवाही या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है। ऐसे माहौल में विरोध-प्रदर्शन होना स्वाभाविक है।

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि वह उनकी बात गंभीरता से सुने।हाल के घटनाक्रम में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ अलग और सख्त कानून लाने की घोषणा की है। परीक्षा सुधारों पर चर्चा की बात भी कही गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से सुधारों की विस्तृत कार्ययोजना मांगी है और स्पष्ट किया है कि केवल अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार जरूरी हैं। यह संकेत है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस बदलाव की अपेक्षा की जा रही है।दूसरी ओर विपक्ष और छात्र संगठनों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी तय हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग इसी संदर्भ में उठाई जा रही है। लोकतंत्र में जवाबदेही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय तथ्यों, जांच और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। केवल राजनीतिक दबाव या जनभावना के आधार पर निर्णय लेना भी दीर्घकालिक समाधान नहीं माना जा सकता।इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू उन छात्रों की मानसिक स्थिति है, जिन्होंने परीक्षा अनिश्चितता और तनाव के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना किया। कई परिवार आर्थिक और भावनात्मक संकट से गुजरे हैं। इसलिए सुधार केवल परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, पारदर्शी शिकायत निवारण और समयबद्ध न्याय पर भी ध्यान देना होगा।संसद का मानसून सत्र बार-बार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, लेकिन संसद का उद्देश्य संवाद और समाधान भी है। यदि सदन नहीं चलेंगे, तो परीक्षा सुधार, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा कैसे होगी? सरकार और विपक्ष—दोनों की जिम्मेदारी है कि वे राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें।

NEET पेपर लीक पर संसद में फिर टकराव विपक्ष अड़ा; सरकार लाई सख्त कानून की तैयारी

NEET पेपर लीक मामले को लेकर मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है।सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून लाने का संकेत दिया है, जबकि विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और प्रधानमंत्री से माफी की मांग पर अड़ा है।हंगामे के बीच राज्यसभा में वंदे मातरम् बिल पेश हुआ, लेकिन दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई।

संसद का मानसून सत्र अब तक NEET पेपर लीक मामले को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है और शुक्रवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। हालांकि इसी बीच राज्यसभा में वंदे मातरम् बिल पेश कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार पेपर लीक की समस्या को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि केवल पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए एक अलग और बेहद सख्त कानून का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार अगले सप्ताह इसे संसद से पारित कराने का प्रयास करेगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही संसद में पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर चर्चा कराने तथा पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से चला आ रहा अपना अनशन समाप्त कर दिया। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि प्रधानमंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देर रात एकतरफा तरीके से अपनी बात रखी। खरगे ने मांग की कि प्रधानमंत्री संसद आने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें और छात्रों से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद की कार्यवाही से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें:वंदे मातरम् बिल पेश होने के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'अभी किरेन रिजीजू ने बयान दिया कि वो चाहते हैं कि हम अपने सांसदों से कहें कि चर्चा होनी चाहिए। नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है, तो उसे जवाब दिया जाता है लेकिन जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, तो फिर मुझसे माइक ले लिया गया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं विपक्ष का रुख स्पष्ट कहना चाहता हूं कि छात्रों की तीन मांगे हैं, पहली मांग भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को जाना होगा, दूसरी जिन लोगों ने छात्रों पर आक्रमण किया, उनपर कार्रवाई हो और तीसरी प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने से पहले कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे।' विपक्ष के भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि सरकार द्वारा बार-बार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा का आश्वासन देने के बावजूद हंगामा जारी रहा।

राहुल गांधी, INDIA गठबंधन के सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे

पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर हमलावर राहुल गांधी आज फिर सड़क पर उतर गए हैं। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ 30 जनवरी मार्ग गांधी स्मृति स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बस में सवार होकर वह विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति स्थल पहुंचे। गांधी स्मृति पहुंचने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हमारे नेता महात्मा गांधी की हत्या यहीं हुई थी। आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। छात्रों पर ज़ुल्म कर रही है और उन्हें पीट रही है। विपक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम छात्रों के साथ हैं और नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा और माफ़ी मांगनी होगी।" वहीं, कांग्रेस नेता और NSUI के सदस्य गांधी स्मृति के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है। कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। हम छात्रों की मांग को उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया। वे बच्चे जिन्हें NEET पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं, जो घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं। पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है। इस बीच राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। यह बैठक NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर संसद में बने गतिरोध के बीच हो रही है, जिसमें विपक्ष ने चर्चा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राज्यसभा के नियम 267 के तहत चर्चा की मांग रखी है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह NEET विवाद और इससे जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष से कोई शर्त न रखने को कहा है। नियम 267 के तहत सांसद संसद के उच्च सदन में कामकाज रोकने की मांग कर सकते हैं। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के साथ बैठक की थी। मीटिंग में TMC ममता गुट के नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और INDIA गठबंधन के अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि गुरुवार को सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और दोनों पक्ष पेपर लीक विवाद पर अपने-अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे।

CJP-सरकार वार्ता में इस्तीफे पर फैसला टला धर्मेंद्र प्रधान पर अड़ा आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए शुक्रवार को अहम बातचीत हुई। मोदी सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ दिल्ली में बैठक की। इस दौरान सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उन्हें पद से हटाएगी। वहीं हमारी दो अन्य मांगों- NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा और छात्रों पर दर्ज FIR व कानूनी मामलों को वापस लेने पर सरकार ने सिद्धांततः सहमति जता दी है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि उसका सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा अब भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और सीजेपी के बीच यह बातचीत तब हुई, जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों की दो शर्तों को स्वीकार करने का संकेत दिया है। इनमें शांतिपूर्ण

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन शामिल है। इसके बावजूद CJP ने दोहराया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं माना जाएगा। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि हमें बताया गया है कि कल शनिवार है, उसके बाद रविवार है, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। इसीलिए सरकार आज रात हमें हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह सरकार की एक और बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि जब वे सोनम वांगचुक को ले गए, तो आंदोलन और मजबूत हो गया। जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और वे घायल हुए, तो विरोध और तेज हो गया। अगर हमें भी हिरासत में लिया गया, तो आंदोलन पूरे देश में और फैल जाएगा। अगर सरकार सच में इस आंदोलन को सुलझाना चाहती है, तो इसका एक ही हल है: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।

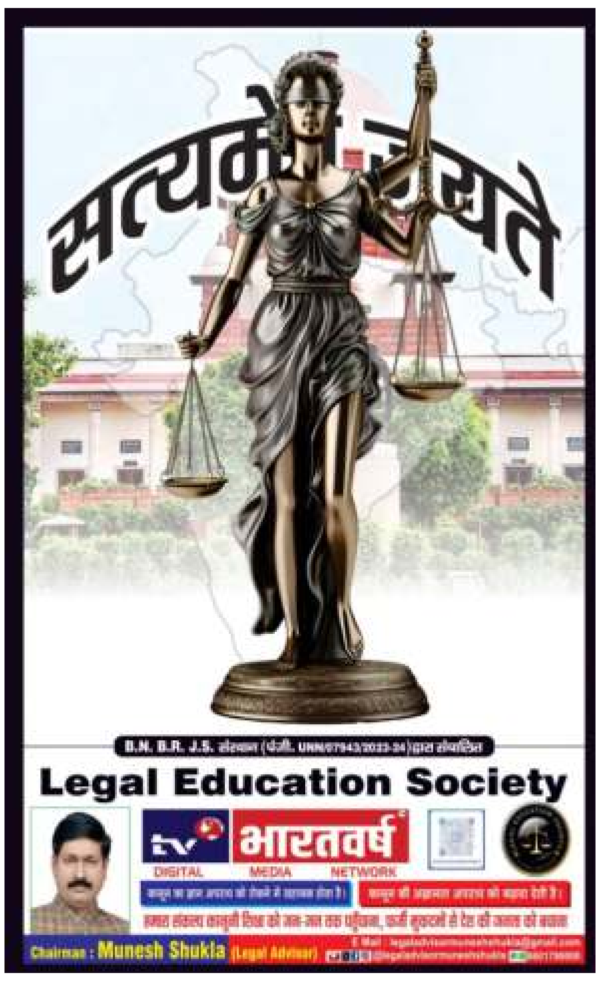

NEET पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त केंद्र से मांगा सुधारों का रोडमैप और नया हलफनामा

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET-UG पेपर लीक के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रोग्रेस पर नया डिटेल्ड हलफनामा (affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट बताया था कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि हलफनामे में कामचलाऊ उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाना चाहिए। केंद्र सरकार अगले साल से नीट यूजी परीक्षा 'कंप्यूटर बेस्ड' (CBT) मोड में कराने की तैयारी कर रही है। इस पर कोर्ट ने प्रस्तावित गवर्निंग बोर्ड, एक्सपर्ट्स के नेतृत्व वाली यूनिट्स, स्टेकहोल्डर के नामांकन और दस क्षेत्रों (जिनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट, पारदर्शिता, प्रशासन और मानव संसाधन शामिल हैं) में हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र से नीट एग्जाम में सुरक्षा, निगरानी और सतर्कता के लिए हाल ही में नियुक्त अतिरिक्त महानिदेशकों (Additional Directors General) की भूमिका और प्रगति के बारे में भी बताने को कहा। बेंच ने एग्जाम साइकिल के हर चरण- परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद में सुधारों पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। कोर्ट ने केंद्र से राज्य और जिला अधिकारियों के साथ टेस्टिंग के तरीकों, कई सेशन में होने वाली परीक्षाओं, परीक्षा केंद्रों, प्रश्न पत्रों, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर हुई प्रोग्रेस की बारीक से बारीक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कंप्यूटर-बेस्ड टेस्टिंग (CBT) में बदलने के प्रस्ताव और डेटा सुरक्षा के उपायों के बारे में भी जानकारी मांगी। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि पेपर लीक के बाद (प्रश्न पत्रों के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए) भारतीय वायु सेना की तैनाती केवल एक कामचलाऊ रास्ता था और यह कोई ठोस प्लान नहीं हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र से उम्मीदवारों के वेरिफिकेशन के लिए डिजीयात्रा (DigiYatra) जैसी तकनीकों पर अपने प्रस्ताव के बारे में भी बताने को कहा। यह देखते हुए कि केंद्र के हलफनामे में इन मुद्दों पर बात नहीं की गई है, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि एक नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, 'हम इस पर बारीकी से नजर रखेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सुधारों को संस्थागत रूप दिया जाए। हम पूरे साल इस पर नजर रखेंगे।'

(NTA) की 1000 से ज्यादा वार्षिक आय की जानकारी सामने आई

देशभर में पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सड़कों पर हैं। नीट एग्जाम पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांग और पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों का मुआवजे की मांग की जा रही है। पेपर लीक के मुद्दे के बीच पारदर्शी और सुचारु ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कमाई सामने आई है। केंद्र सरकार ने एनटीए की कमाई का रिपोर्ट कार्ड खोला है। हाल ही में सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी से पता चलता है कि बीते पांच में एनटीए की कमाई दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 2019-20 में जहां एनटीए की आय 504.16 करोड़ रुपये थे, वहीं 2023-24 में बढ़कर 1,116.84 करोड़ रुपये पहुंच गई है। सरकार ने संसद को यह भी बताया कि 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से, NTA ने 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिनमें 6.6 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।बीते बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने NTA का आय-व्यय विवरण (Income and Expenditure Account) पेश किया। इसे 'अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम' (Accrual Accounting System) के तहत तैयार किया गया था और एजेंसी की गवर्निंग बॉडी ने इसे मंजूरी दी थी।

भारत की स्टार जूडोका तूलिका मान को नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी ने प्रोविजनल रूप से सस्पेंड कर दिया

हरभजन सिंह ने नीट पेपर लीक को लेकर पोस्ट शेयर किया

नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इस मुद्दे पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हरभजन ने एक्स पर लिखा, "सोनम वांगचुक जी को अपना अनशन समाप्त करते देखकर खुशी हुई। गतिरोध के बजाय बातचीत और बंटवारे के बजाय आपसी भरोसा हमेशा बेहतर रास्ता होता है। बेहतर शिक्षा का सपना देखने वाला हर छात्र एक मजबूत भारत का सपना देख रहा है। आइए, हम सहानुभूति के साथ सुनें, बातचीत करें और स्थायी समाधान की दिशा में मिलकर काम करें। हमारे युवा इससे कम के हकदार नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे जो हमारे युवाओं और देश के सर्वोत्तम हित में हो। जय हिंद।" हरभजन ने अपने इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद रखा, जिसके बाद यूजर्स ने पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, "मालिक कमेंट सेक्शन तो खोलो, जरा सुनो तो जनता आपके बारे में क्या सोचती है।" दूसरे ने कहा, "अगर आप इतने सच्चे इंसान हैं तो कमेंट सेक्शन क्यों बंद किया है?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप आलोचना से डरते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे हरभजन सिंह ने हाल ही में आप का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, जहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे।

भारत के साथ चार टीमों को सीधे नॉकआउट में एंट्री

जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के पुरुष और महिला क्रिकेट इवेंट का ड्रॉ घोषित कर दिया गया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को पुरुष इवेंट में सीधा क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। सीडिंग के आधार पर यह फैसला हुआ है। इनके साथ क्वार्टर फाइनल में चार अन्य टीमें क्वालिफाइंग राउंड से पहुंचेंगी। एशियन गेम्स में क्रिकेट का आयोजन टी20 फॉर्मेट में किया जाएगा।क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल को जगह मिली है। वहीं ग्रुप बी में हांगकांग, मलेशिया और ओमान है। क्वालिफाइंग राउंड में सभी टीमें अपने-अपने ग्रुप में एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी। दोनों ग्रुपों की टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। अफगानिस्तान ने 2023 में सिल्वर मेडल जीता था। महिला क्रिकेट इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनके बीच सीधे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेला जाएंगे। पाकिस्तान का सामना थाईलैंड से होगा तो मलेशइया और श्रीलंका की भिड़ंत होगी। चीन और बांग्लादेश के साथ ही भारत और जापान की टक्कर होगी। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम के बीच ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला होगा। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में क्रिकेट के मुकाबले होंगे। महिला इवेंट की शुरुआत 17 सितंबर को होगी। फाइनल मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं 24 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच पुरुष क्रिकेट खेला जाएगा। भारत ने पिछली बार ने पुरुष के साथ ही महिला इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। टीम एक बार फिर गोल्ड मेडल की दावेदार है।

अल्जारी जोसफ ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाएगा। इससे पहले एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसफ ने खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। इस बात का खुलासा टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की ओर से टीम का ऐलान किया गया है। इस बीच वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने कहा है कि अल्जारी जोसफ ने पाकिस्तान के खिलाफ दो मैच खेलने से मना किया है। सैमी ने कहा कि जोसेफ ने खुद ही खेलने से इन्कार किया है। सैमी बोले कि जोसफ चोट से वापसी कर रहे है और अब वे खेलना चाहते तो उन्हें टीम में हर हाल में चुना जाता, लेकिन वे उन्होंने मना किया है। इससे टीम को नुकसान होगा। जब सैमी से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया। साथ ही ये भी जोड़ा कि ये फैसला उनके निजी अधिकारों से बाहर का है। सैमी ने कहा कि ये निर्णय वेस्टइंडीज बोर्ड करेगा कि अगर कोई खिलाड़ी सीरीज खेलने इन्कार करता है तो क्या करना चाहिए। अल्जारी जोसफ वेस्टइंडीज बोर्ड के अनुबंधित खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनका ये फैसला भारी भी पड़ सकता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो टीम पहले ही वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। पहला मैच 25 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम साढ़े सात बजे से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेलना जाना है, जो कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इस बार डब्ल्यूटीस यानी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिक में पाकिस्तान टीम सबसे नीचे हैं, वेस्टइंडीज की टीम उससे एक पायदान आगे है। यानी दो नीचे की टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। जाहिर है कि जब मैच खत्म होगा, तब अंक तालिका की रैंकिंग में नहीं तो कम से कम पीसीटी में तो बदलाव जरूर आएगा।

थरूर ने क्यों शेयर किया अमिताभ का 14 साल पुराना ट्वीट

NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज है. इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को एक्टर अमिताभ बच्चन का 2012 का एक ट्वीट रीपोस्ट किया. इस ट्वीट में UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की गई थी.थरूर ने X पर यह पोस्ट बिना अपनी कोई टिप्पणी जोड़े शेयर किया.

2012 के उस ट्वीट में लिखा था: 'T 970 - दिल्ली में जो हो रहा है उसे देखकर दुख और हैरानी हो रही है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब आंसू गैस और वॉटर कैनन से दिया जा रहा है.' अमिताभ ने यह संदेश दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद देश भर में मचे आक्रोश के दौरान शेयर किया था, जब इंडिया गेट और रायसीना हिल के पास प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई थी. इस बार की बात करें तो शबाना आजमी, प्रकाश राज और स्वरा भास्कर समेत कुछ अभिनेता सीधे तौर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट से जुड़े हैं.

प्यार के लिए छोड़ी लग्जरी लाइफ

कहते हैं प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है. कोई देश बदल देता है, तो कोई अपना करियर छोड़ देता है. लेकिन अमेरिका के एक युवक ने प्यार के लिए अपनी आरामदायक जिंदगी ही छोड़ दी.

उसने शहर की भागदौड़ और आधुनिक सुविधाओं को अलविदा कह दिया और अब अपनी पत्नी के साथ अमेजन के घने जंगलों में एक आदिवासी समुदाय के बीच रह रहा है. आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है.डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 साल के जस्टिन अल्वो की मुलाकात मारिया से इक्वाडोर में हुई थी.

मारिया अमेजन के शुआरो आदिवासी समुदाय से हैं और उस समय एक अमेजनियन रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर काम करती थीं. दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और आखिरकार शादी कर ली. अब यह कपल पूर्वी इक्वाडोर के अमेजन वर्षावन में रहता है.

दोनों अपने रोजमर्रा के जीवन और आदिवासी संस्कृति की झलक अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिखाते हैं.

पिता की वजह से पहुंचे थे अमेजन

जस्टिन अमेरिका में पले-बढ़े हैं. हालांकि, उनका अमेजन से भी एक खास रिश्ता है. उन्होंने बताया कि उनके पिता का बचपन इक्वाडोर के एक दूरदराज के आदिवासी इलाके में बीता था.

टेक ऑफ होते ही खिड़की टूटी, प्लेन से बाहर आधा लटका पैसेंजर

आसमान में मौत से मुकाबला

एक फ्लाइट के टेकऑफ होते ही प्लेन की एक खिड़की टूट गई और उसके विंडो के पास बैठा पैसेंजर खींचकर आधा बाहर लटक गया. अगर सीट बेल्ट बंधी ना होती तो शख्स पूरा बाहर निकल सकता था.

सोचिए, आपने अभी-अभी फ्लाइट में सीट बेल्ट बांधी हो, विमान ने उड़ान भरी हो और अचानक जोरदार धमाके के साथ आपकी सीट के पास की खिड़की टूट जाए.

तेज हवा का दबाव आपको विमान से बाहर खींचने लगे और आपका आधा शरीर हवा में लटक जाए. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीस से जर्मनी जा रही एक रयानएयर की फ्लाइट में 61 साल के एक यात्री के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. यह हादसा इतना भयावह था कि शख्स सदमे में चला गया. 10 जुलाई को सर्बिया के कारोबारी ल्यूबिशा कारोविच ग्रीस से जर्मनी जा रही रयानएयर की फ्लाइट में सफर कर रहे थे. उनकी सीट 11F थी, जो खिड़की के पास थी. टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद अचानक उनकी सीट के पास लगी खिड़की का शीशा टूट गया. इसके बाद केबिन का एयर प्रेशर तेजी से गिरा और तेज हवा के दबाव ने उन्हें खिड़की की ओर खींच लिया. कारोविच के मुताबिक, उन्हें सबसे ज्यादा उस जोरदार धमाके की आवाज याद है. उन्होंने कहा कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, वही धमाके की आवाज कानों में गूंजने लगती है. उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत कम याद है.

पत्नी और यात्रियों ने बचाई जान

हादसे के वक्त कारोविच की पत्नी स्वेतलाना उनसे तीन पंक्ति पीछे बैठी थीं. धमाका सुनते ही वह दौड़कर उनके पास पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उनके पति करीब डेढ़ से दो मिनट तक आधे विमान के अंदर और आधे बाहर लटके रहे.स्वेतलाना का कहना है कि उस समय दूसरे यात्रियों ने मिलकर उनके पति को अंदर खींचा. एक यात्री ने पहले बैग से टूटी खिड़की को बंद करने की कोशिश की.

प्रदर्शनकारियों के लिए बेनामी ऑर्डर की बाढ़

दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में इन दिनों एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है. यहां हर कुछ मिनट में जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर खाने के पैकेट लेकर पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि ये ऑर्डर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वहां मौजूद किसी भी भूखे प्रदर्शनकारी के लिए किए जा रहे हैं.

देशभर से आ रहे ऑनलाइन फूड ऑर्डर: रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, जयपुर कई अन्य शहरों से लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं.

'रामायण' का ट्रेलर 24 जुलाई को नहीं होगा रिलीज

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने किया ऐलान

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में 'रामायण' पैनल के लिए स्टेज पर जाने से कुछ ही मिनट पहले प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने घोषणा की कि फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज नहीं होगा। यह अचानक आई खबर फैंस के लिए एक सरप्राइज थी, जो कॉमिक-कॉन प्रीमियर के बाद इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के ट्रेलर के ऑनलाइन आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

दिल्ली में हुआ था भव्य ट्रेलर लॉन्च

हाल ही में दिल्ली में 18 जुलाई को नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का भव्य ट्रेलर लॉन्च किया गया

पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर सपा का बड़ा अभियान सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी

पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।समाजवादी पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाने और विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।पार्टी का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।

उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) अब अपने आंदोलन को व्यापक रूप देने की तैयारी में है। पार्टी ने तय किया है कि इन विषयों को केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाकर युवाओं और छात्रों के बीच भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए विवादों और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है। ऐसे में सरकार से जवाबदेही तय कराना और युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाना आवश्यक है।पार्टी सूत्रों के अनुसार, आगामी दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों, अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से सीधे संवाद किया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं और सुझावों को एकत्र कर उन्हें राजनीतिक और विधायी मंच पर उठाने की रणनीति तैयार की जा रही है। सपा का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए इन मुद्दों पर व्यापक जनचर्चा जरूरी है।यूपी विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में भी समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के विधायक पेपर लीक की घटनाओं, भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं। पार्टी का कहना है कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो इसका सीधा असर उनके भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास पर पड़ता है।इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सपा अपने विभिन्न फ्रंटल संगठनों को भी सक्रिय करने जा रही है। पार्टी का छात्र संगठन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेगा और उनकी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास करेगा। वहीं युवजन सभा को जिला और तहसील स्तर पर जनजागरण कार्यक्रम चलाने तथा युवाओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य सहयोगी संगठन स्थानीय स्तर पर बैठकें, ज्ञापन और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं से जुड़े मुद्दे हमेशा चुनावी और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। पेपर लीक, भर्ती में देरी और परीक्षा संबंधी विवाद ऐसे विषय हैं, जिनका असर सीधे लाखों छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन मुद्दों के जरिए युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यदि यह अभियान व्यापक स्तर पर चलता है, तो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुख बहस का विषय बन सकते हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है और विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर किस तरह की चर्चा देखने को मिलती है।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा

लखनऊ के इको गार्डन में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, पेपर लीक के मामलों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महासचिव अनिकेत धनुक ने किया। अनिकेत धनुक ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाना गलत है। पार्टी आंदोलन जारी रखेगी। हम लखनऊ को नया जंतर-मंतर बना देंगे। अनिकेत धनुक ने कहा कि यह धरना प्रतीकात्मक नहीं बल्कि छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और छात्रों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना होगा। प्रदेश महासचिव ने बताया कि शनिवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इको गार्डन पहुंचकर आंदोलन में शामिल होंगे। उनके आने के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। अनिकेत धनुक ने कहा कि यदि सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन और व्यापक होगा। उन्होंने कहा, हम लखनऊ को नया जंतर-मंतर बना देंगे। यह धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता और उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

लोकभवन के गेट नंबर-9 के सामने 2 लोग आत्मदाह का प्रयास,मच गया हड़कंप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुरक्षा के घेरे में बंधे हजरतगंज इलाके में एक बाद फिर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लोकभवन के गेट नंबर-9 के सामने 2 लोग आत्मदाह का प्रयास करने पहुंचे। हालांकि, सचिवालय के सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते दोनों को मौके पर पकड़ लिया और उनके पास मौजूद ज्वलनशील पदार्थ अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि आत्मदाह का प्रयास करने वाले दोनों लोग लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रिश्ते में चाचा-भतीजे लगते हैं। पीड़ितों का कहना है कि वह अपनी जमीन कब्जा होने और शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया।लखनऊ के मलिहाबाद तहसील स्थित दुबग्गा थाना क्षेत्र के लीलाखेड़ा कटौली के रहने वाले राम गणेश और उनके भतीजे सतीश कुमार गौतम ने शुक्रवार सुबह लोकभवन के सामने पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस टीम और सचिवालय की सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें समय रहते बचा लिया। दोनों को हजरतगंज थाने ले आए। पूछताछ में पीड़ित राम गणेश ने बताया कि गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन पर उनके परिवार के ही सुनील नाम के व्यक्ति ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है। जमीन कब्जा होने के बाद से वे लगातार 6 साल से परेशान हैं और अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।दुबग्गा थाना क्षेत्र के रहने वाले दोनों पीड़ितों में बताया कि वे साल 2020 से लगातार DM और SDM के दफ्तर के चक्कर काट कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने व जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद उन्होंने परेशान होकर आत्मदाह करने का फैसला लिया। इस मामले पर हजरतगंज थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ितों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही इस घटना की आला अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है।

अविमुक्तेश्वरानंद ने शुक्रवार को लखनऊ में गो-संरक्षण आंदोलन के अगले चरण का ऐलान किया

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने शुक्रवार को लखनऊ में गो-संरक्षण आंदोलन के अगले चरण का ऐलान किया। उन्होंने 'गो गर्जना अक्षौहिणी संकल्प' सभा में कहा कि देश के गांव-गांव तक गोमाता के लिए आंदोलन चलेगा। यूपी के एक लाख सात हजार गांवों से गोमाता लखनऊ लाएंगे। उन्हें सीएम योगी से मिलाएंगे। इस बार आंदोलन के लिए सरकार से अनुमति नहीं मांगेंगे। 17 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। 17 नवंबर को बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में जुटेंगे। यहां 11 दिन रहेंगे। उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा-हमारे आंदोलन के लिए सरकार को मैदान और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। बीते 11 मार्च को लखनऊ में आयोजित 'शंखनाद सभा' के दौरान 24 जुलाई को बड़े कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। आयोजन समिति का कहना है कि औपचारिकताएं 3 जुलाई को पूरी कर ली गई थीं। जब 36 घंटे पहले तक अनुमति नहीं मिली तो समर्थकों से गो गर्जना अक्षौहिणी संकल्प सभा को विधानसभा क्षेत्र स्तर पर करने के लिए कहा गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि 14 से 17 अगस्त (श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया से पंचमी) तक छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधियों का सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 17 अगस्त से प्रदेश और देशभर में 'एक नोट अभियान' शुरू किया जाएगा। इसके तहत हर व्यक्ति से आंदोलन के लिए एक नोट का सहयोग देने की अपील की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 'गो माता के नाम कांवड़ यात्रा' निकालने का अभियान भी शुरू किया जाएगा, ताकि गो-संरक्षण के प्रति लोगों को जोड़ा जा सके।

लखनऊ में कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी

लखनऊ में कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देर रात में झमाझम बरसात होने से तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। गुरुवार को दिन में 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून में लखनऊ में अभी तक 38 फीसदी सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। इस दौरान कुल बारिश 165.1 मिलीमीटर हुई है। सामान्य बारिश का औसत 253.5 मिलीमीटर है। भारतीय मौसम विभाग (I M D) के अनुसार आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे। शहर के कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसूनी हवाओं की मुख्य लाइन फिलहाल सामान्य से काफी दक्षिण की ओर खिसक गई है। यह जैसलमेर, कोटा, गुना और मध्य प्रदेश-बिहार के दक्षिणी हिस्सों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। इसी वजह से मानसून का मुख्य जोर अभी पश्चिम और मध्य भारत की तरफ शिफ्ट हो गया है।

69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव

उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक भर्ती एक बार फिर विवादों में आ गई है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नौकरी और आरक्षण की मांग को लेकर लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे और वहां घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने 'योगी बाबा न्याय करो' के नारे लगाए। इसके बाद पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 6800 सीटों के मामले में सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एफिडेविट दाखिल किया है, जिससे उनके साथ न्याय नहीं हो रहा प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में 21 प्रतिशत दलित और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों को लेकर गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द नियुक्ति देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी हाथों में अलग-अलग स्लोगन लिखे बैनर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने 'योगी बाबा न्याय करो' और 'हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो' जैसे नारे लगाए। इसी दौरान एक अभ्यर्थी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं, अपने छोटे बच्चे के साथ प्रदर्शन में पहुंची एक महिला अभ्यर्थी के बच्चे को पुलिसकर्मियों ने गोद में लेकर संभाला। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। अभ्यर्थियों ने पुलिस पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। करीब 30 मिनट तक चले विवाद के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। कुछ अभ्यर्थियों को हाथ-पैर पकड़कर उठाया गया और बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। प्रदर्शन में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में यह केस लड़ रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में, सरकार हम सभी को OBC और पिछड़े समुदायों से अलग करने की कोशिश कर रही है। ये अधिकारी बार-बार ऐसे हलफनामे (affidavits) जमा करते हैं जिनसे हमारी एकता तोड़ने और हमें अलग-अलग गुटों में बांटने की कोशिश की जाती है। इससे पहले, इन्हीं अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने 6,800 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है। उन्होंने हाई कोर्ट में यह भी माना था कि 6,800 सीटों के आवंटन को लेकर एक समस्या थी।

हसनगंज में सपा का पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ मजबूत करने पर जोर

उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र स्थित एक लॉन में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) का पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग तीन घंटे तक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सम्मेलन में नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्यामलाल पाल ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सफलता की कुंजी बूथ स्तर की मजबूती है। उन्होंने प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष से अपने-अपने क्षेत्र में संगठन को सशक्त बनाने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि बूथ मजबूत होगा तो विधानसभा और प्रदेश में जीत का मार्ग भी आसान होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मेलन विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है तथा आम जनता, युवाओं और बेरोजगारों की आवाज उठाना पार्टी की प्राथमिकता है। श्यामलाल पाल ने हाल के छात्र आंदोलनों और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है और केवल अधिकारियों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की समस्याओं का समाधान करने और प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को पहुंचाने का आह्वान किया।

शुक्लागंज में सफल रथ यात्रा के बाद समिति अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला का सम्मान

उन्नाव के शुक्लागंज में 26वीं श्रीमद् भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के सफल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन के बाद शुक्रवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजधानी मार्ग स्थित सब्जी मंडी परिसर में हुए इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों, श्रद्धालुओं और रथ यात्रा समिति के पदाधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला का सम्मान किया। उन्हें पुष्पमालाएं पहनाई गईं और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। श्रीमद् भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 26 सालों से शुक्लागंज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। इस साल भी हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लिया। आयोजन के दौरान सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व, दूरदर्शिता और प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय की सराहना की। उनके प्रयासों के कारण ही यात्रा का संचालन सफलतापूर्वक हो सका। समिति के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों, पुलिस प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से यात्रा के प्रत्येक चरण पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वीरेंद्र शुक्ला ने सभी नगरवासियों, समिति के सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया।

उन्नाव में रेलवे फाटक 35-बी 26 जुलाई तक बंद

उन्नाव में लखनऊ-कानपुर रेलमार्ग पर स्थित रेलवे फाटक संख्या-35 बी को ट्रैक और क्रॉसिंग की मरम्मत के लिए 26 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। छोटे चौराहे से लोकनगर जाने वाले इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक और क्रॉसिंग के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के कारण फाटक को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए इस अवधि में किसी भी वाहन को फाटक से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य रेल संचालन को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी है। यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। छोटे चौराहे से लोकनगर जाने वाले वाहन चालक छोटा चौराहा–कचहरी रोड–ओवरब्रिज मार्ग का उपयोग करें। वहीं, लोकनगर और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों के लिए भी यही मार्ग निर्धारित किया गया है। फाटक बंद होने के कारण छोटे चौराहा, लोकनगर, स्टेशन रोड और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके और जाम की स्थिति न बने।

कांवड़ यात्रा-2026 से पहले उन्नाव में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

श्रावण मास और कांवड़ यात्रा-2026 को देखते हुए उन्नाव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे गांधी नगर तिराहा से शुरू हुए अभियान में नगर पालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान जेसीबी से अस्थायी ढांचे हटाए गए और दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे, टीन शेड, फुटपाथ पर रखा सामान और नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कई दुकानदारों ने कार्रवाई से पहले ही अपना सामान स्वयं हटा लिया, जबकि शेष स्थानों पर नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) रामाश्रय ने बताया कि अभियान शासन और जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करना और शहर की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि नाली से नाली तक किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। फुटपाथ पर रखा सामान भी हटवाया जा रहा है, ताकि पैदल यात्रियों और वाहनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शुक्रवार को गांधी चौराहे से बड़ा चौराहा होते हुए नगर पालिका कार्यालय तक कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। अगले चरण की रूपरेखा समीक्षा के बाद तय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, अभियान शुरू करने से पहले संबंधित क्षेत्रों में मुनादी कराकर लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूरे अभियान के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कहीं भी कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित नहीं हुई। प्रशासन ने व्यापारियों और आम नागरिकों से सड़क, फुटपाथ और नालियों पर अतिक्रमण न करने तथा शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

उन्नाव में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, कटान से तटवर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता

उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर शुक्रवार को एक बार फिर बढ़ गया। हालांकि यह अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन नवीन गंगा पुल से रेलवे पुल के बीच तेज कटान ने तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 10 बजे गंगा का जलस्तर 109.750 मीटर दर्ज किया गया था। शुक्रवार सुबह 8 बजे भी जलस्तर 109.750 मीटर रहा, लेकिन दोपहर 12 बजे तक इसमें 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे जलस्तर 109.800 मीटर हो गया। पिछले कई दिनों से घट रहे जलस्तर में यह वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। इसका मुख्य कारण उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश तथा विभिन्न बैराजों से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा है। यदि ऊपरी इलाकों में लगातार वर्षा होती है, तो नदी का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ सकता है। जलस्तर में बदलाव के साथ ही गंगा किनारे कटान की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। नवीन गंगा पुल से रेलवे पुल के बीच कई स्थानों पर तेज बहाव के कारण तटों की मिट्टी लगातार कट रही है। इससे नदी किनारे स्थित खेतों और खाली भूमि को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। किसानों ने चिंता व्यक्त की है कि यदि समय रहते कटान रोधी कार्य नहीं किए गए, तो उनकी कृषि भूमि बरसात के दौरान नदी में समा सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग से कटान प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और तत्काल सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में कटान कभी भी गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए पहले से तैयारी करना आवश्यक है।

बृजभूषण पर भाजपा विधायक का पलटवार, बोले- उम्र के साथ कमजोर हो गई याददाश्त

उन्नाव में भाजपा विधायक अनिल सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की उम्र अधिक हो गई है और उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में अयोध्या की हनुमानगढ़ी को लेकर बयान दिया था कि "हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई।" इसी बयान पर पुरवा विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने अपनी राय रखी। अनिल सिंह ने कहा, "बृजभूषण दादा की उम्र हो गई है। वह अब 72 साल के हो गए हैं। 72 साल की उम्र में आदमी बहुत सी बातें भूल जाता है। उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है।" विधायक ने आगे कहा, "वो अपने आपको मुख्यमंत्री से बड़ा नेता मानते हों, यह अलग बात है। यह उनका बड़बोलापन हो सकता है, लेकिन हर मामले में बोलने की उनकी आदत है। उनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता।" अनिल सिंह ने यह बयान शुक्रवार को उन्नाव शहर के आजाद मार्ग स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ मेमोरियल इंस्टीट्यूट में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी कृति राज, जिला पंचायत अध्यक्ष सुकून सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

UP Scholarship 2026-27: 11 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी टाइमलाइन

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।कक्षा 9 से 12 तक के पात्र छात्र 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि सत्यापन और जांच की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी।नवीनीकरण वाले छात्रों को अक्टूबर 2026 और नए आवेदकों को जनवरी 2027 तक PFMS के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि मिलने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) योजना का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य वर्ग (General) और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 11 अगस्त 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।छात्रवृत्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 5 अगस्त 2026 तक अपना मास्टर डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और संबंधित अधिकारी विद्यालयों द्वारा अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। इसी अवधि में अल्पसंख्यक वर्ग के निजी शिक्षण संस्थानों की पोर्टल पर मार्किंग की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, ताकि पात्र संस्थानों के विद्यार्थियों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल सके।विभाग ने नवीनीकरण (Renewal) श्रेणी के छात्रों के लिए अलग समय-सारिणी तय की है। ऐसे छात्र 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की हार्डकॉपी अपने विद्यालय में जमा करेंगे। इसके बाद विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक सत्यापन, आवेदन की जांच और उसे आगे भेजने की प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 31 अगस्त से 10 सितंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक वास्तविक छात्र संख्या का सत्यापन करेंगे, जबकि 11 से 17 सितंबर के बीच राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी की जाएगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा डाटा लॉक होने के बाद पात्र छात्रों के खातों में अक्टूबर 2026 के अंत तक PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि भेजना शुरू कर दिया जाएगा।वहीं पहली बार आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवेदन और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। नए आवेदनों की जांच, सत्यापन और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होने के बाद जनवरी 2027 में पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि सीधे PFMS सिस्टम के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अधूरी जानकारी या दस्तावेजों में कमी मिलने पर संबंधित छात्र को सुधार का अवसर दिया जाएगा। सुधार के बाद आवेदन का दोबारा सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृत होगी।समाज कल्याण विभाग ने सभी छात्रों से अपील की है कि आवेदन करते समय अपना नाम, आधार, बैंक खाता, शैक्षणिक विवरण और अन्य जानकारी पूरी तरह सही भरें। साथ ही आवेदन की हार्डकॉपी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने, दस्तावेज अधूरे रखने या समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी पात्र छात्र समय-सारिणी का पालन करते हुए समय पर आवेदन करें, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सके।

पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुक्रवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गंगोह थाना क्षेत्र के नया गांव स्थित फैक्ट्री में हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य के घायल होने की सूचना है। विस्फोट इतना भीषण था कि शवों के चीथड़े करीब 100 मीटर दूर तक जा गिरे, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट के तुरंत बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की कई टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। विस्फोट के कारण फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राहत एवं बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहा है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर बचाव अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन की ओर से अभी तक मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना

नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक एक्स पोस्ट में BJP और उसके समर्थकों को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अब लोग भाजपा को लेकर पहले जैसे उत्साहित नहीं हैं और पार्टी समर्थकों में भी नाराजगी बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब लोगों के दिल-दिमाग से उतर जाएगी। उन्होंने युवाओं, लोकतंत्र, महंगाई, रोजगार और कई अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक तरफ तो भाजपा और उनके संगी-साथी अपने लोगों को प्रोटेस्टर्स के बीच भेजकर युवाओं को गलत साबित करने में लगे हैं, दूसरी तरफ जब उन्हें भाजपाई कहा जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके समर्थक युवाओं के आंदोलनों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कई समर्थक भी पार्टी के फैसलों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के समर्थक अब जनता में BJP के प्रति नाराजगी को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर जाने से बच रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भाजपा के पेड एंड अनपेड समर्थक भी अब पार्टी के बचाव में आगे नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कट्टर समर्थकों ने पिछले 10-12 सालों में पार्टी का बचाव किया, लेकिन अब वे भी भाजपा की नीतियों और फैसलों से निराश हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट में CEO पद के लिए 5 हजार से ज्यादा लोगों ने किया अप्लाई

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक महीने में सीईओ मिल जाने की उम्मीद है। इस पोस्ट के लिए पांच हज़ार से ज़्यादा लोगो ने अप्लाई किया है।अप्लाई करने वालों को अब 25 जुलाई तक गूगल फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म में 32 सवाल हैं। फॉर्म में नाम ,पता ,उम्र ,पेशा, काम करने का अनुभव तो पूछा ही गया है, साथ में ये भी पूछा गया है कि क्या आप सच्चे हिंदू हैं? सीईओ पद के लिए आवेदन फॉर्म में यह भी पूछा गया है कि क्या आपने कोई मेगा इवेंट किया है, अगर किया है तो मेगा इवेंट में कितने लोग शामिल हुए? क्या आप किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन अथवा मंदिर से जुड़े हैं?आपने कितने वर्ष तक किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन अथवा मंदिर का प्रबंधन किया है? आपके द्वारा प्रबंधित सामाजिक या धार्मिक संगठन या मंदिर का आकार कितना था? उन धार्मिक संगठनों या मंदिरों का नाम और अपनी ज़िम्मेदारी बताइए। साथ में फॉर्म में प्रोफ़ेशनल, सामाजिक और मंदिर से जुड़े अनुभव के सत्यापन के लिए कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम, पद और संपर्क विवरण मांगा गया है। फॉर्म में यह भी पूछा गया है कि कितने कर्मचारी आपके लीडरशिप में काम करते थे? आपको कौन-कौन से इनाम, पुरस्कार मिले? श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए विज़न, प्लान और सुझाव भी पूछे गए हैं। फॉर्म के साथ सीवी लगानी है और दो लोगो का रेफरेंस देना है। मंदिर का सीईओ चुनने के लिए ट्रस्ट ने तीन मेम्बर के सेलेक्ट कमेटी बनाई है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे हैं। सेलेक्ट कमेटी ने 13 जुलाई को सीईओ की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे। सीईओ के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। जानकारी के मुताबिक, सिलेक्शन में किसी खास एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बजाय कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया जाएगा। ट्रस्ट का मानना है कि व्यक्ति को एक अच्छा मैनेजर, काबिल एडमिनिस्ट्रेटर और विनम्र होना चाहिए, साथ ही उसके पास अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और संबंधित अनुभव होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है। कमेटी ने यह भी साफ़ किया कि कोई भौगोलिक प्राथमिकता नहीं होगी। भारतीय नागरिकता ही एकमात्र योग्यता मानदंड होगी।